1966-67 :—अपील में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय देने तक 4 प्रतिशत का अन्तरिम भुगतान ।

दिल्ली क्लाथ मिल के लाभ के आंकड़े अलग रूप से प्राप्त नहीं हैं ।

(ग) 1962-63 तथा 1963-64 का बोनस यूनियनों के साथ किए गये एक समझौते के फलस्वरूप दिया गया जबकि 1964-65 का 6 प्रतिशत की दर से घोषित किया गया बोनस, प्रबन्धकों के अनुसार, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के उपबन्ध के आधार पर निकाला गया । 1965-66 तथा 1966-67 वर्षों के लिए प्रबन्धकों ने बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत दिया जाने वाले 4 प्रतिशत का न्यूनतम बोनस दे दिया है, क्योंकि 1964-65 के बोनस सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में अभी भी विचाराधीन है ।

(घ) जी नहीं ।

दिल्ली क्लाथ मिल्स के मजदूरों की मंजूरी

7648. **श्री निहाल सिंह :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मजूरी बोर्ड ने दिल्ली क्लाथ मिल्स के मजदूरों के लिये नये मजूरी दरों के नियत किये जाने की सिफारिश की थी परन्तु उनकी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार नियत नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उपरोक्त कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड ने किन वेतन मानों की सिफारिश की थी और गत तीन वर्षों में उन को क्या पुनरीक्षित वेतनमान दिये गये हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं । प्रबन्धकों ने कपड़ा उद्योग के पहले केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू कर दिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मजूरी बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए वेतन-मानों और मजूरी-दरों के संबंध में सूचना मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट में उपलब्ध है, जिसकी प्रतियां 1960 से बाजार में उपलब्ध हैं । श्रमिकों को वास्तव में किए गए वेतन-मान विभिन्न पद-श्रेणियों के अनुसार, जिनमें वे नियुक्त हैं, भिन्न-भिन्न हैं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी तथा चावल मिल

7649. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चीनी तथा चावल के कुल कितने, अलग-अलग, मिल हैं; और

(ख) उनमें कुल कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं और कितने नियमित कर्मचारी हैं और कितने अस्थायी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चीनी मिलें 205

चावल मिलें-हुलर 44,036

शैलर 2,649

हुलर और शैलर मिश्रित 3,810

कुल 50,495

(ख) चीनी मिलों में काम कर रहे व्यक्तियों की संख्या लगभग 2.05 लाख है । चीनी मिलों में काम कर रहे नियमित और अस्थायी कर्मचारियों के बारे में अलग-अलग सूचना उपलब्ध नहीं है । चावल मिलों में काम

कर रहे कर्मचारियों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

Rodent Control Campaign

7650. SHRI M. S. OBEROI :
SHRI K. LAKKAPPA :

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Pests Control Association has, in consultation with the Government, decided to set up a Committee to draw up proposals for evolving a nationwide rodent control campaign ;

(b) if so, the outlines of the proposed programme ; and

(c) the nature of assistance proposed to be given by Government to that Committee in their projected campaigning ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) No, Sir. The Government of India have not been consulted by the Indian Pest Control Association for the setting up of any Committee for rodent control.

(b) and (c) Does not arise.

Recommendations of National Labour Commission's Study Group

7651. SHRI M. S. OBEROI : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether a Study Group of the National Labour Commission has recommended to Government that fertiliser industry should be placed under the control of the Central Government in respect of labour legislation ;

(b) if so, the details of the proposals made and what would be its implications ; and

(c) whether State Governments will be consulted before taking a final decision in the matter ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI) : (a) Yes.

(b) The proposals are for the consideration of the National Commission on Labour.

(c) The Commission will consult all interests concerned, including the State Governments.

Complaint from Eastern Railwaymen's Union

7652. SHRI DEVEN SEN : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on a complaint from the Eastern Railwaymen's Union Asansol, an enquiry has been institutituted by his Ministry about violation of labour laws regarding extra hours of work performed and non-payment of overtime for the same ; and

(b) if so, the stage at which the investigations are at present ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI) : (a) No. A complaint has however received from some employees of the Easter Railway (Asansol Division), and it is being enquired into.

(b) The report in the matter is expected shortly.

Newspaper Employees' Organisation Demand for the Implementation of Wage Boards Recommendations.

7653. SHRI DEVEN SEN :
SHRI SITARAM KESRI :
SHRI RAMAVATAR SHASTRI:
SHRI BENI SHANKER SHARMA :

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Central Co-ordination Committee of the Newspapers Employees' Organisations, in a meeting at Calcutta on the 31st March, 1968, has decided to start an indefinite strike in newspapers all over the country to demand implementation of the recommendations of the Wage Board's for —Journalists and non-journalists ; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter ?